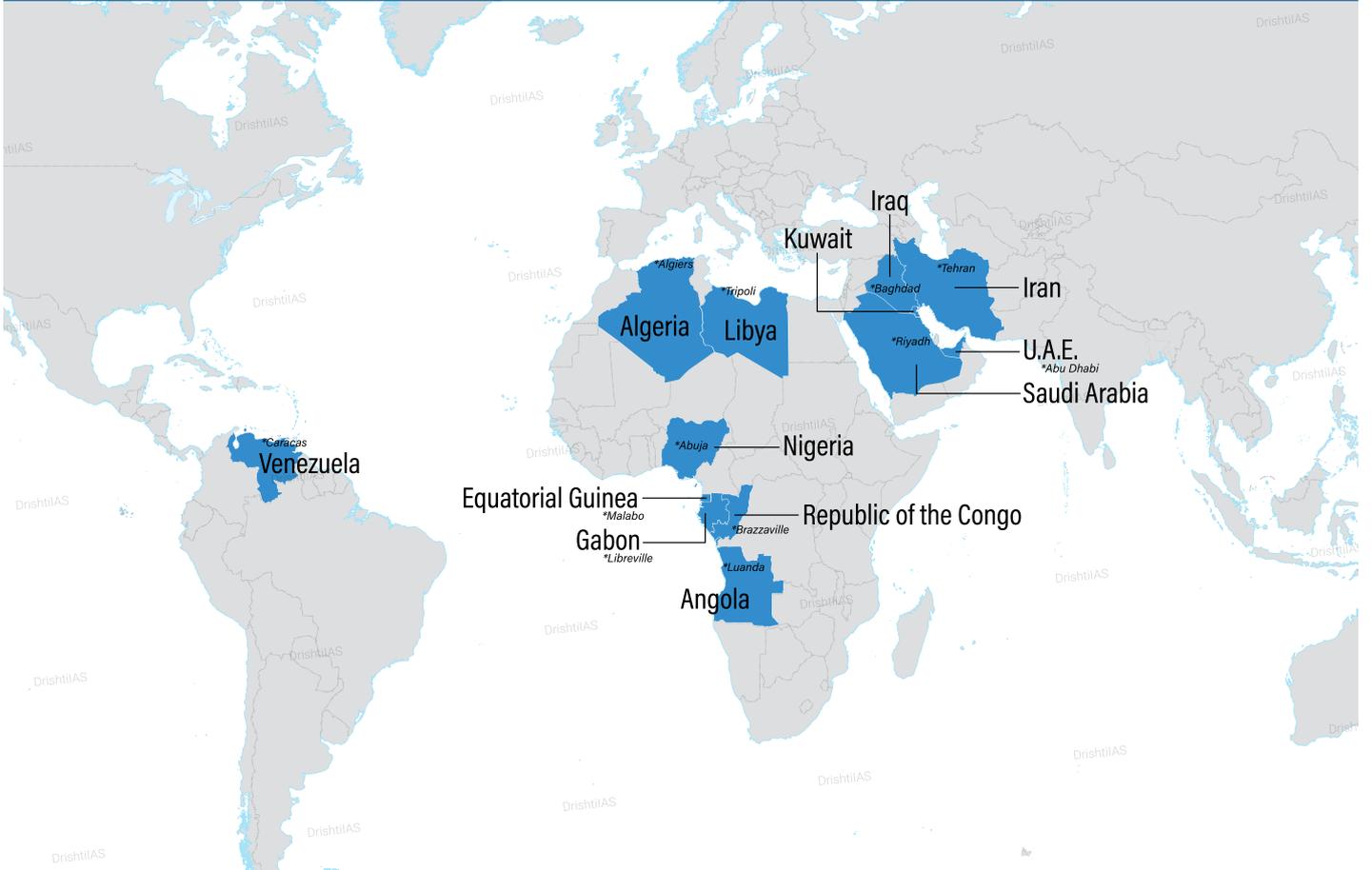


## पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)

# पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)



- बगदाद सम्मेलन (1960) में बनाया गया अंतर सरकारी संगठन
- मुख्यालय - वियना, ऑस्ट्रिया
- वर्तमान सदस्य - 13 (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला)
- वे देश जो सदस्यता को छोड़ चुके हैं - इक्वाडोर (2020), कतर (2019), इंडोनेशिया (2016)
- सदस्यता - वह कोई भी देश जो 'पेट्रोलियम का पर्याप्त मात्रा में निर्यात करता है, इसका सदस्य बन सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिये ओपेक फंड - विश्व स्तर पर एकमात्र अनिवार्य विकास संस्थान जो सदस्य से लेकर गैर-सदस्य देशों को विशेष रूप से वित्तपोषण प्रदान करता है।

# पृथ्वी का आंतरिक भाग

## 1 क्रस्ट

- सबसे पतली, सबसे बाहरी परत
- सागरीय क्रस्ट - पतली
  - औसत मोटाई - 5 कि.मी.
  - सिलिका और मैग्नीशियम ( SiMa ) से निर्मित है,
- महाद्वीपीय क्रस्ट - मोटी
  - औसत मोटाई - 30 कि.मी.
  - सिलिका और एल्युमीनियम ( SiAl ) से निर्मित है,
  - प्रमुखतः पर्वत श्रेणियों के क्षेत्रों में इसकी मोटाई अधिक है,
    - हिमालयी क्षेत्र में लगभग 70 कि.मी. मोटाई है
- गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है ( प्रत्येक किमी पर 30° C तक )

### लिथोस्फीयर

- मोटाई: 100 कि.मी., बाहरी परत कठोर
- क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनता है
- पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिये जिम्मेदार विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित ( फोल्डिंग, फॉल्टिंग )

## 3 क्रोड

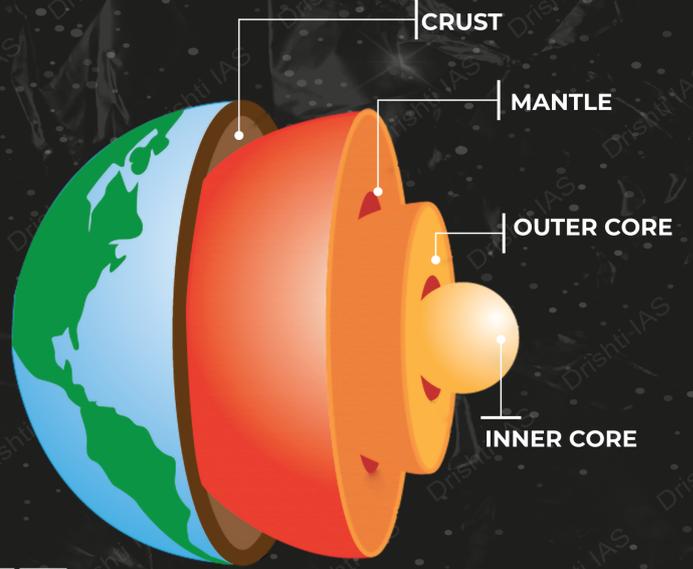
- पृथ्वी की सतह के नीचे 2900-6400 कि.मी. के बीच स्थित है,
- मुख्य रूप से भारी पदार्थों से बना है, जैसे- निकल ( Ni ) और लोहा ( Fe ) - NiFe
- बाहरी क्रोड -
  - 2900-5100 कि.मी. के बीच
  - ठोस में परिवर्तित होने के लिये पर्याप्त दबाव नहीं होने के कारण तरल है
- आंतरिक क्रोड -
  - 5100-6370 कि.मी. के बीच
  - ठोस - यह द्वितीयक तरंगों ( भूकंप ) को प्रसारित कर सकता है जिसे बाहरी क्रोड नहीं कर सकता
- मेंटल की तुलना में सघन

### पृथ्वी की परतों के बीच की असंबद्धताएँ

1. कोनराड असंबद्धता - ऊपरी और निचली भूपर्पटी के बीच
2. मोहोरोविकिक असंबद्धता ( मोहो ) - भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है, इसकी औसत गहराई लगभग 35 कि.मी. है।
3. रेपटी असंबद्धता - ऊपरी और निचले मेंटल के बीच
4. गुटेनबर्ग असंबद्धता - मेंटल और बाहरी कोर के बीच स्थित है।
5. लेहमैन असंबद्धता - आंतरिक और बाहरी कोर के बीच

## 2 मेंटल

- मोहो असंबद्धता से 2,900 कि.मी. की गहराई तक फैली हुई है,
- ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है,
  - कमजोर चट्टानों का क्षेत्र; अर्द्ध पिघला हुआ अथवा जेली ( अर्द्ध द्रवीय ) अवस्था में
  - 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है,
  - मैग्मा का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट होता है



## पुनर्रचकरण शृंखला में रेडियोधर्मी पदार्थ

### प्रलिमिंस के लिये:

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), IAEA परमाणु सुरक्षा योजना, नोबेल शांतिपुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र महासभा, UPSC, IAS, सविलि सेवा परीक्षा।

### मेन्स के लिये:

## चर्चा में क्यों?

[अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी](#) (International Atomic Energy Agency- IAEA) ने [परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ/सामग्री](#) की अवैध तस्करी पर वार्षिक डेटा जारी किया है।

- इस डेटा से पता चलता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ या दूषित उपकरण तेज़ी से बढ़ते स्करैप पुनर्चक्रण शृंखला में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हो रहा है।

## प्रमुख बटु

- IAEA की [परमाणु सुरक्षा योजना](#) परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी की घटनाओं की रिपोर्ट करने हेतु बनाई गई थी।
- इस नवीनतम डेटासेट से पता चलता है कि रेडियोधर्मी स्रोतों के अनधिकृत निपटान की घटनाएँ स्करैप धातु या अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योगों में बढ़ रही हैं।
  - ऐसी घटनाएँ रेडियोधर्मी सामग्री के न्यंत्रण, सुरक्षित और उचित निपटान हेतु प्रणालियों में कमियों को इंगित करती हैं।
- यदि घरेलू सामानों के निर्माण हेतु परणामी दूषित धातु का उपयोग किया जाता है, तो इससे उपभोक्ताओं को संभावित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।
  - IAEA ने वर्ष 2022 में 146 ऐसी घटनाओं की सूचना दी जो वर्ष 2021 के आँकड़े से लगभग 38% अधिक है।

## रेडियोधर्मी सामग्री को पुनर्चक्रण शृंखला में शामिल होने से रोकने के उपाय:

- **नियामक ढाँचे को मज़बूत बनाना:** रेडियोधर्मी सामग्री के उचित संचालन, भंडारण और निपटान सुनिश्चित करने के लिये सरकारों को अपने नियामक ढाँचे एवं प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है।
  - इसमें रेडियोधर्मी सामग्री को प्रबंधित करने वाली नकियों के लिये सख्त लाइसेंसिंग और गैर-अनुपालन के मामले में दंड का प्रावधान शामिल किया जा सकता है।
- **नगिरानी और न्यंत्रण तंत्र में सुधार:** [परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्रियों की अवैध तस्करी](#) को रोकने के लिये सरकारों को नगिरानी तथा न्यंत्रण तंत्र में सुधार हेतु भी नविश करना चाहिये।
  - इसके अंतर्गत सीमाओं और प्रवेश के अन्य बटुओं पर वकिरण का पता लगाने वाले उपकरणों का उपयोग करना, अधिक व्यापक ट्रैकिंग एवं रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं।
- **वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना:** सरकारों और अन्य हतिधारकों को रेडियोधर्मी संदूषण का जोखिम पैदा न करने वाले वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से रेडियोधर्मी अपशिष्टों से आवश्यकता वाली सामग्रियों निकालने के लिये प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिये।

## रेडियोधर्मिता:

- रेडियोधर्मिता कुछ तत्त्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन तीन प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा।
  - अल्फा कण धनावेशित हीलियम (He) परमाणु हैं, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं और गामा किरणें उदासीन वदियुत चुंबकीय वकिरण हैं।
- रेडियोधर्मी तत्त्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम तीन 'NORM' (स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री) शृंखलाएँ हैं जो जल संसाधनों को संदूषित करते हैं।
- रेडियोधर्मिता को बेकुरल (SI इकाई) या क्यूरी में मापा जाता है। यूनिट सीवर्ट मानव ऊतकों द्वारा अवशोषित वकिरण की मात्रा को मापता है।

## अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी:

- **परिचय:**
  - इसे [संयुक्त राष्ट्र](#) के अंदर व्यापक रूप से विश्व में 'शांति और विकास हेतु संगठन' के रूप में जाना जाता है, IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिये एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र है।
- **स्थापना:**
  - IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में [परमाणु प्रौद्योगिकी](#) के विविध उपयोगों से उत्पन्न आशंकाओं और खोजों की प्रतिक्रिया में की गई थी।
  - **मुख्यालय:** वियना (ऑस्ट्रिया)
- **उद्देश्य:**
  - यह एजेंसी अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, नशित और शांतपूरण उपयोग को बढ़ावा देने के लिये काम करती है।
  - वर्ष 2005 में एक सुरक्षित और शांतपूरण विश्व के निर्माण में इसके योगदान के लिये IAEA को [नोबेल शांतिपुरस्कार](#) से सम्मानित किया

गया था ।

■ कार्य:

- यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो **संयुक्त राष्ट्र महासभा** को वार्षिकी रूप से रिपोर्ट करता है ।
- जब आवश्यक हो IAEA सुरक्षा उपायों एवं सुरक्षा दायित्वों का सदस्यों द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों के संबंध में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** को भी रिपोर्ट करती है ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संदर्भ में 'अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.)' के साथ 'अतिरिक्त नयाचार (एडसिनल प्रोटोकॉल)' का अनुसमर्थन करने का नहितारथ क्या है? (2018)

- (a) असैन्य परमाणु रिएक्टर आई.ए.ई.ए. के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं ।
- (b) सैनिक परमाणु अधिष्ठान आई.ए.ई.ए. के नरीक्षण के अधीन आ जाते हैं ।
- (c) देश के पास नाभकीय पूरतकिरत्ता समूह (एन.एस.जी.) से यूरेनियम के कर्य का वशिषाधिकार हो जाएगा ।
- (d) देश स्वतः एन.एस.जी.का सदस्य बन जाता है ।

उत्तर: (a)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

## हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधनियिम, 2023

### प्रलिमिंस के लयि:

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधनियिम, 2023

### मेन्स के लयि:

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधनियिम, 2023 के लाभ और महत्त्व

## चरचा में क्यों ?

हमिचल प्रदेश ने **अनाथों** और वशिष रूप से ज़रूरतमंदों का कल्याण सुनशिचति करने के लयि सुखाश्रय (राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं आत्मनरिभरता) अधनियिम, 2023 पारति कयि है ।

## सुखाश्रय अधनियिम, 2023 के मुख्य बदि:

■ परिचय :

- यह अधनियिम ऐसे बच्चों जनिहें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, **जनिके माता-पति नहीं हैं या माता-पति अक्षम हैं, को अनाथ** के रूप में परिभाषति करता है । इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जनिके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखमि में हैं ।
- यह अधनियिम **18-27 वर्ष की आयु के बीच के लाभार्थियों को** व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल वकिस और अनुशिक्षण के साथ समाज के सकरयि सदस्य बनने में मदद करने हेतु **वत्तीय तथा संस्थागत लाभ** प्रदान करता है ।
- अधनियिम समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा एवं देखभाल सुनशिचति करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।

■ अधनियिम के तहत लाभ:

- **101 करोड रुपए परवियय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है** तथा योजना की देख-रेख के लयि प्रत्येक ज़लि में एक बाल कल्याण समति की स्थापना की जाएगी ।
- इसके तहत अनाथ एवं वशिष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे '**राज्य के बच्चे**' माने जाएंगे ।
- इसके तहत वत्तीय लाभ में गर्मियों एवं सर्दियों में **5,000 रुपए**, प्रमुख त्योहारों हेतु **500 रुपए** तथा कॉलेज में दैनिक खरच के लयि **4,000 रुपए मासकि भत्ता** शामिल है ।
- संस्थागत लाभों में ट्रेन टकिट और राज्य के भीतर **10 दिनों के लयि आवास** तथा ITI एवं सरकारी कॉलेजों में लाभार्थियों हेतु

छात्रावास शुल्क शामिल है।

- सरकार, शादी के समय तय रकम तथा अपना घर बनाने के लिये तीन बसिवा ज़मीन प्रदान करेगी।
- अनाथ जो अपने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक सांकेतिक कोष प्रदान किया जाएगा।
  - पीएच.डी. छात्रों को मासिक भत्ता भी मलिया।

■ अधिनियम में उल्लिखित अन्य सुरक्षा उपाय:

- बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व नविसियों को 21 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा एवं राज्य सरकार इन खातों में प्रचलित दरों के अनुसार अंशदान करेगी।
- बाल कल्याण समिति अनाथों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करेगी एवं ज़रूरतमंद बच्चों की मांगों पर गौर करेगी।

**नोट:** कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, देश में अनाथ एवं नरिशरति बच्चे "देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (Children in Need of Care and Protection- CNCP) हैं। अधिनियम के नष्पादन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

## केंद्र सरकार की समान पहल:

■ बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services- CPS) योजना या "मशिन वात्सल्य":

- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- CPS के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।
- इस योजना के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions- CCI) में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।
- यह योजना गैर-संस्थागत देखभाल भी प्रदान करती है जिसमें गोद लेने, पालन-पोषण, देखभाल और प्रायोजन (Sponsorship) हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## RBI का ग्रीन डिपॉज़िट फ्रेमवर्क

### प्रलिमिंस के लिये:

ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम, ग्रीन बॉण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार।

### मेन्स के लिये:

ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम।

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम (GFS) विकसित करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिये ग्रीन डिपॉज़िट (हरति जमा) की पेशकश करने हेतु एक नए फ्रेमवर्क (ढाँचा) की घोषणा की है।

- यह ढाँचा 1 जून, 2023 से लागू होगा।
- ग्रीन डिपॉज़िट (हरति नकिषेप) निश्चित अवधि के लिये एक वनियमिती इकाई (Regulated Entity-RE) द्वारा प्राप्त ब्याज-युक्त जमा को संदर्भित करता है, जिसमें ग्रीन फाइनेंस (हरति वित्तपोषण) के आवंटन हेतु नरिधारति आय होती है।

## ढाँचे की प्रमुख वशिषताएँ:

#### ■ पर्योज्यता:

- यह ढाँचा कषेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय कषेत्र के बैंकों, भुगतान बैंकों तथा आवास वित्त कंपनियों के साथ-साथ सभी जमा स्वीकार करने वाली [गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों \(Non-Banking Financial Companies- NBFCs\)](#) को छोड़कर लघु वित्त बैंकों सहित अनुसूचति वाणज्यिक बैंकों पर लागू होता है।

#### ■ आवंटन:

- REs को हरति गतविधियों एवं परयोजनाओं की एक सूची हेतु ग्रीन डिपॉज़िट के माध्यम से संग्रहीत आय को आवंटति करने की आवश्यकता होगी जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहति करते हैं, कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीनहाउस गैसों को कम करते हैं, जलवायु लचीलापन और/या अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं तथा प्राकृतिक पारस्थितिक तंत्र एवं जैवविविधता में सुधार करते हैं।

#### ■ अपवर्जन:

- जीवाश्म ईंधन के नए या मौजूदा **नषिकर्षण, उत्पादन और वतिरण** से जुड़ी परयोजनाओं हेतु ग्रीन फाइनेंसिंग उपलब्ध नहीं है, जिसमें सुधार तथा उन्नयन, परमाणु ऊर्जा, प्रत्यक्ष अपशषित भस्मीकरण, शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग या ताड़ तेल उद्योग, संरक्षति कषेत्रों में उत्पन्न फीडस्टॉक का उपयोग करके **बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परयोजनाएँ, लैंडफिल परयोजनाएँ या 25 मेगावाट से बड़े जलवदियुत संयंत्र** शामिल हैं।

#### ■ वतिपोषण ढाँचा:

- हरति जमा/ग्रीन डिपॉज़िट का प्रभावी आवंटन सुनिश्चति करने हेतु RE को बोर्ड द्वारा अनुमोदित **वतिपोषण ढाँचा (Financing Framework- FF)** स्थापति करना चाहिये। ग्रीन डिपॉज़िट को केवल भारतीय रुपए में मूल्यवर्गति कथि जाएगा।
- वतितीय वर्ष के दौरान RE द्वारा ग्रीन डिपॉज़िट के माध्यम से एकात्रति धनराशा का आवंटनस्वतंत्र **तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन के अधीन** होगा, जो वार्षिक आधार पर कथि जाएगा।

## ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम:

#### ■ परिचय:

- GFS वतितीय प्रणाली को संदर्भति करता है जो पर्यावरणीय रूप से **स्थायी परयोजनाओं और गतविधियों में निवेश का समर्थन एवं उन्हें सक्षम बनाता है।**
- इसमें कई प्रकार के वतितीय उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि **ग्रीन बॉण्ड, ग्रीन लोन, ग्रीन इश्योरेंस और ग्रीन फंड** जो पर्यावरण के अनुकूल वधियों एवं परयोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु तैयार कथि गए हैं।
- ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम का उद्देश्य एक ऐसी वतितीय प्रणाली बनाना है जो **कम कार्बन, संसाधन-कुशल और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में संक्रमण** में सहयोग करती है, जबकि **जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैवविविधता क्षति** जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े जोखिमों तथा अवसरों को भी शामिल करता है।

#### ■ आवश्यकता:

- संसाधन जुटाने और हरति गतविधियों/परयोजनाओं हेतु आवंटन में वतितीय कषेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। **भारत में ग्रीन फाइनेंस उत्तरोत्तर गति तथा लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।**
- जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए और ग्रीनवाशि चितियों को दूर करते हुए GFS हरति गतविधियों और परयोजनाओं के लिये **ऋण प्रवाह में वृद्धि** कर सकता है।
- साथ ही यह **भारत में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव** के लिये **सतत विकास** को बढ़ावा दे सकता है।

#### ■ भारतीय परिदृश्य:

- भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करने की दशा में काम करना शुरू कर दिया है और **'ग्रीन डील'** इसी दशा में एक कदम है।
  - ग्रीन डील ने डीकार्बोनाइज़ेशन में तेज़ी लाने के लिये **ग्रीन फाइनेंस** को एक सक्षमकर्त्ता के रूप में वर्गीकृत कथि है। यह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापति करने के लिये **सरकार और नजी संस्थाओं से पूंजी प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।**
- वर्ष 2016 में RBI ने स्थायी वतितीय प्रणालियों की तर्ज़ पर UNEP (**संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम**) और भारत के सहयोग के संबंध में एक रपौट जारी की थी।
  - यह रपौट भारत में वतितीय प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं और हरति वति/ग्रीन फाइनेंस में तेज़ी लाने में इसकी भूमिका का आकलन करती है।
- **'परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड'** स्कीम के ज़रिये देश के नीतगित ढाँचे में कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत की गई है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, **वर्ष 2023 तक ग्रीन बॉण्ड का बाज़ार दो ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है।**

## संबंधति पहलें:

- **वदिशी पूंजी को प्रोत्साहन:** सरकार ने अक्षय ऊर्जा कषेत्र में स्वचालति मार्ग के तहत 100% तक **प्रत्यक्ष वदिशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहति करना:**
  - सरकार ने इन परयोजनाओं के लिये सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री हेतु अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) शुल्क माफ कर दिया है।
  - **नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा करय बाध्यता (RPO)** के लिये प्रावधान करना और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना।
  - **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन** की घोषणा।
- **भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारति योगदान:** वर्ष 2015 में हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा अपनाए गए पेरिस समझौते के तहत भारत ने

नरिधारति लक्ष्यों के साथ [राषट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDC\)](#) परस्तुत कयिा था ।

- अपने [सकल घरेलू उतपाद \(GDP\)](#) की उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33-35% तक कम करना ।
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईधन आधारति ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% तक संचयी वदियुत शक्ति क्षमता प्राप्त करना ।

## आगे की राह

- भारत में हरति अर्थव्यवस्था आशाजनक संकेतकों के साथ वसितार कर रही है और बैंक सक्रयि रूप से स्थायी वतित को बढावा देने के साथ-साथ देश को न्यूनतम कार्बन, संसाधन-कुशल तथा टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दशिा में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिा रहे हैं ।
- हरति परयोजनाओं का वतितपोषण एक सतत् भवषिय प्राप्त करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/13-04-2023/print>

